भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 465
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मुरादाबाद विमानपत्तन का उन्नयन

***465. श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंधा पांडे विमानपत्तन पर उड़ानों का संचालन 05 दिसंबर, 2024 से निलंबित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 'क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान' के तहत जोड़े जाने वाले लक्षित शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 'उड़ान' योजना के तहत कुल कितने मार्ग आवंटित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त मार्गों से कुल कितनी आय अर्जित हुई है; और

(घ) सरकार ने इस तथ्य के दृष्टिगत कि लोग मुरादाबाद में पीतल और हस्तशिल्प व्यवसाय के लिए आते हैं, मुरादाबाद को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य महानगरों से विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"'मुरादाबाद विमानपत्तन का उन्नयन" के संबंध में श्रीमती रुचि वीरा द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 465 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत फ्लाईबिग एयरलाइन द्वारा दिनांक 10.08.2024 को मुरादाबाद-लखनऊ मार्ग पर उड़ान परिचालन शुरू किया गया था। तथापि, एयरलाइन ने उत्तर भारत में कम दृश्यता के कारण दिनांक 03.11.2024 से उड़ान परिचालन बंद कर दिया। वर्तमान में, लखनऊ हवाईअड्डे पर चरणबद्ध तरीके से पुनर्सतहीकरण का कार्य चल रहा है और दिन के समय रनवे बंद रहता है, चूंकि मुरादाबाद एक वीएफआर हवाईअड्डा है, इसलिए उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग): सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुलभ बनाने/प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 13 हेलीपोर्ट और 02 वाटर एयरोड्रोम सहित 88 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 625 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया जा चुका है। आरसीएस-उड़ान योजना के माध्यम से 2.97 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में 149 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है।
सरकार ने अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों की यात्रा को सुलभ बनाने के लिए अपनी संशोधित 'उड़ान योजना' शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी।
सरकार उड़ान मार्गों का प्रचालन करके कोई राजस्व अर्जित नहीं करती है।

(घ): 'उड़ान' मांग-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत एयरलाइन ऑपरेटर किसी विशेष मार्ग पर परिचालन की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं और समय-समय पर योजना के अंतर्गत बोली लगाते हैं। यदि कोई एयरलाइन भविष्य की बोली प्रक्रिया में मुरादाबाद को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य मेट्रो शहरों से जोड़ने वाली आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर 'उड़ान योजना' के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें अपनी वाणिज्यिक और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने, सेवा प्रदान करने की अपनी इच्छानुसार किसी भी बाजार और नेटवर्क/मार्ग का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****